पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5615

संजीव कुमार चंदरियावी, श्री नवल किशोर प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-कागज़ी के निवासी,
डाक घर और थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपने महानिबंधक के माध्यम से।
2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, पटना।
3. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से।
4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।
5. अवर सचिव-I, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

हेडनोट

बिहार सेवा संहिता, 1952 - नियम 74 - न्यायिक पदाधिकारी का अनिवार्य सेवानिवृत्ति - याचिकाकर्ता ने उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दिया है - याचिकाकर्ता जिसे शुरू में सिविल जज (कनिय कोटि) के रूप में नियुक्त किया गया था वह सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पदोन्नत हुआ और उसके तुरंत बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया। जाँच को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अचानक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उसे

न्यूनतम सेवा शर्तों की पूरी नहीं करने के कारण पेंशन से वंचित होने की स्थिति को भी इस रिट के माध्यम से चुनौती दी है। खंडपीठ ने प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य(2010)10 एस.सी.सी. पर भरोसा करते हुये यह माना कि नियम 74(ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति सजाकारी नहीं है - फिर यह निर्मित किया गया कि याचिकाकर्ता पेंशन से इस कारण से वंचित नहीं हुआ है कि उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया, बलिक इस कारण कि उसकी अनिवार्य सेवानिवृति के समय उसके पास न्यूनतम योग्यता सेवा नहीं थी। यह स्थिति नहीं हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसके पास सेवानिवृति पर पेंशन को सक्षम करने वाली न्यूनतम योग्यता सेवा नहीं है, उसे नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृति के लिये विचार नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद कि वह निरंतरता के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है और सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के लिये उत्तरदायी है - याचिकाकर्ता नियम 74 बी.(ii) के तहत निर्धारित तीन महीने की अवधि के दौरान नोटिस वेतन पाने का हकदार है - चूँकि अनिवार्य रूप से सेवानिवृति दंडात्मक प्रकृति का नहीं है, इसलिये याचिकाकर्ता निलंबन अवधि के दौरान देय पूरे वेतन का हकदार है। रिट याचिका को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज किया गया- [पारा 1,4,18,34,35 और 39]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5615

संजीव कुमार चंद्रियावी, श्री नवल किशोर प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-कागज़ी के निवासी,
डाक घर और थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपने महानिबंधक के माध्यम से।
2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, पटना।
3. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से।
4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।
5. अवर सचिव-I, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए:-

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए:-

श्री मनीष कुमार, जीपी-4

श्री मनोज कुमार, जी.पी. 4 के सहायक सलाहकार

उच्च न्यायालय के लिए:- श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सी.ए.वी. निर्णय

तिथि: 18-01-2024

एक न्यायिक अधिकारी जो अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, इस न्यायालय के समक्ष सेवा से उसके निष्काषन को चुनौती दे रहा है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार सिंह पेश हुए और उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने का तर्क दिया। याचिकाकर्ता जिसे शुरू में सिविल जज (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त किया गया था, वह 2022 का पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. था वह सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पदोन्नत हुआ और उसके तुरंत बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आरोपों पर आधारित था जिसके संबंध में जांच शुरू की गई थी। जाँच को आगे बढ़ाया गया और विभाग के साक्ष्य पूरे किए गए। जबकि, अचानक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया तथा निलंबन भी स्थगित कर दिया गया और अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। विद्वान वरिष्ठ सलाहकार उस जल्दबाजी तरीके के पहलू पर जोर देंगे जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई थी, विशेष रूप से जब जांच अपराधी कर्मचारी के साक्ष्य के स्तर पर थी। जहाँ तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का संबंध है, प्रसादपर्दत के सिद्धांत को शून्य में या बाहरी विचारों पर लागू नहीं किया जा सकता है। जब आरोप लगाए जाते हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो अनिवार्य रूप से इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना पड़ता है।

3. विद्वान वरिष्ठ सलाहकार इस तथ्य पर जोर देंगे कि अधिकारी पेंशन से भी वंचित रखा गया क्योंकि उसने न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी। याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति इसलिए कलंकित और दंडात्मक है और इसे बेकार लोगों को हटाने के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब वह अपने निलंबन से ठीक पहले पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया था। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत धारणा और दुर्भावना से प्रेरित और किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी के रूप में उनका आचरण ठीक था।

4. अनिवार्य सेवानिवृत्ति बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत विशेष रूप से नियम 74 के तहत की गई है, जिसके प्रावधान के लिए आदेश पारित होने से पहले राज्य सरकार की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता केवल 50 प्रतिशत वेतन अर्जित कर रहा था और इस प्रकार वह नियम 74 के तहत प्रावधान के अनुसार नोटिस वेतन से भी वंचित था। 1 से 8 और 10 और 12 तक के आरोप लगाए गए थे और आरोप 11 विशिष्ट था जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी जिसे अचानक रोक दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं:

- (i) एम. एस. बिंद्रा बनाम भारत संघ और अन्य; (1998) 7 एससीसी 310,
- (ii) कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज बनाम भारत संघ और एक अन्य; 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 234,
- (iii) अभय जैन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए और एक अन्य (2022) 13 एस. सी. सी. 1,

(iv) गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात स्टील ट्यूब
मजदूर सभा और अन्य; (1980) 2 एस. सी. सी. 593।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान स्थायी सलाहकार श्री पीयूष लाल ने प्रस्तुत किया कि भले ही प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटा दिया गया हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने पर विचार किया जा सकता है, बिना कलंक और इसे सजा के रूप में माने बिना, जैसा कि **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम बिहारी लाल, 1994 पूरक (3) एस.सी.सी-593** में माना गया है, जब कोई अधिकारी संदिग्ध सत्यनिष्ठा का हो। यदि बहुत सारे आरोप हैं, भले ही वे घरेलू जांच शुरू करने की अव्यावहारिकता के कारण बंद कर दिए गए हों, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू की जा सकती है, जैसा एक अन्य कि **अरुण कुमार गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और दूसरा; (2020) 13 एससीसी 355** में कहा गया है। घोर प्रकृति के आरोपों को जवाबी हलफनामे से इंगित किया गया था जो एक के बाद एक अधिकारी के खिलाफ उठाए गए थे। अधिकारी के दोषमुक्त होने पर लगाए गए किसी भी आरोप को बंद नहीं किया गया था। आरोपों में से एक के कारण एक चेतावनी भी जारी की गई थी और आरोप संख्या 11 अपने आप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गारंटी देने के लिए पर्याप्त गंभीर था।

6. दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है और दिमाग का उपयोग न करने का कोई आधार नहीं हो सकता है; विशेष रूप से अधिकारी के आचरण पर विचार करते हुए जैसा कि उसके खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों से पता चलता है। याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी था और एक सामान्य सरकारी कर्मचारी के विपरीत संप्रभु कार्य करता था। यह **प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य और अन्य; (2010) 10 एस. सी. सी. 693** में यह माना गया है कि अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा और ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति न्याय वितरण

प्रणाली के लिए एक दायित्व होगा। ऐसी परिस्थिति में ही बेकार है की चीजों को हटाने का उपाय अपनाया जाता है। ऐसे उदाहरणों में से एक विषय आदेश है, जिसे रिट याचिका में चुनौती दी गई है। विभिन्न आरोपों से पता चलता है कि अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध थी। उनके न्यायिक कौशल के साथ-साथ निष्पक्षता पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते थे, जैसा कि आरोप याचिकाओं से पता चलता है।

7. जहाँ तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विषय नियम 74 (2) के तहत है, नियम 74 (1) का प्रावधान लागू नहीं होता है। निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाता है, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और आरोपों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विद्वान स्थायी सलाहकार सजा के क्रम को बनाए रखने की कोशिश करेगा और अनुरोध करेगा कि इसमें हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं है।

8. कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज (उपरोक्त) एक मामला था। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले के कानून का विश्लेषण किया, विशेष रूप से केंद्रीय सिविल सेवाओं पर लागू मौलिक नियम के संदर्भ में। मौलिक नियम में किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित में सूचना देकर या या नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रावधान दो तत्वों को प्रस्तुत करता है-पहला, किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का सरकार का पूर्ण अधिकार और दूसरा, ऐसा करने के लिए जनहित की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता।

9. इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम इलाहाबाद बैंक (1996) 4 एस. सी. सी. 504 में निर्णय पर भरोसा किया गया संविधान के अनुच्छेद 310 में शामिल प्रसादपर्यंत के सिद्धांत के पहलुओं में से एक के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की शक्ति का

पता लगाने के लिए; उद्देश्य सेवा में दक्षता और पहल बनाए रखने के लिए मृत लकड़ी को निकालना और उन लोगों की सेवाओं को भी वितरित करना है जिनकी ईमानदारी संदिग्ध है; ताकि प्रशासन में शुद्धता बनी रहे। यह माना गया कि “जबकि कदाचार और प्रभावहीनता ऐसे कारक हैं जो खाते में प्रवेश करते हैं जहां आदेश बर्खास्तगी या हटाने या सेवानिवृत्ति का है, यह अंतर है कि जबकि सेवानिवृत्ति के मामले में वे केवल पृष्ठभूमि और जांच प्रस्तुत करते हैं, यदि आयोजित किया जाता है-और जांच करने का कोई कर्तव्य नहीं है-केवल उन अधिकारियों की संतुष्टि के लिए है जिन्हें कार्रवाई करनी होती है, बर्खास्तगी या हटाने के मामले में वे वही आधार बनाते हैं जिन पर कार्रवाई की जाती है। आदेश दिया गया है, जैसा कि इस न्यायालय ने श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1955)1 एस.सी.आर 26 और बॉम्बे राज्य बनाम सौयम्यचंद एम.दोशी। 9582 एस.सी.आर. 57 में बताया है।

10. **स्वामी सरन सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; (1980) 1 एस. सी. सी. 12** एक ऐसा मामला था जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया गया था, क्योंकि न्यायालय कुछ महीने पहले कर्मचारी द्वारा दूसरी दक्षता सीमा को पार करने में स्पष्ट विरोधाभास को दूर करने में असमर्थ था; माना जाता है कि उसने विशिष्ट क्षमता और ईमानदारी के साथ काम किया था; जिसके कुछ महीनों के बाद वह अयोग्य पाया गया और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया।

11. **राम एकबाल शर्मा बनाम बिहार राज्य; (1990) 3 एस. सी. सी. 504** का अभिनिर्धारण इस प्रकार किया गया था:

“उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने पर अब जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह है कि भले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सरकारी कर्मचारी, जिसे अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया है, के खिलाफ कोई आरोप लगाए बिना हानिरहित भाषा में दिया गया है, अदालत, यदि

चुनौती दी जाती है, तो उचित मामलों में यह पता लगाने के लिए पर्दा उठा सकती है कि क्या आदेश संबंधित सरकारी कर्मचारी के किसी कदाचार पर आधारित है या आदेश को प्रामाणिक बनाया गया है और किसी भी अप्रत्यक्ष या बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं।”

12. नंद कुमार वर्मा बनाम झारखंड राज्य (2012) 3 एस. सी. सी. 580 में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

“यह भी स्पष्ट है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राय का गठन संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होती है लेकिन ऐसी संतुष्टि एक वैध सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालयों को यह पता लगाने की अनुमति है कि क्या कोई वैध सामग्री मौजूद है या अन्यथा, जिस पर प्रशासनिक प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि आधारित है।”

13. जैसा कि निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ (2020) 13 एससीसी 56, में माना गया है कि परीक्षा के लिए वास्तविक परीक्षा क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जुर्माना है या उस आड़ में बर्खास्तगी, "यह देखने के लिए है कि क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अनुपयुक्तता की चिंता से उत्पन्न होता है या कदाचार के लिए सजा के रूप में"।

14. गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम.पटेल; (2001) 3 एस. सी. सी. 314 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को चित्रित किया:

“11. अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून अब एक निश्चित सिद्धांत में परिवर्तित हो गया है, जिसे मोटे तौर पर इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

- (i) जब भी किसी लोक सेवक की सेवाएँ सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, तो लोक हित के लिए अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
- (ii) आम तौर पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत आने वाली सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- (iii) बेहतर प्रशासन के लिए, मृत लकड़ी को काटना आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकारी का पूरा सेवा अभिलेख के संबंध में होने के बाद पारित किया जा सकता है।
- (iv) गोपनीय अभिलेख में की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि पर ध्यान दिया जाएगा और इस तरह के आदेश को पारित करने में उचित महत्व दिया जाएगा।
- (v) गोपनीय अभिलेख में असंबद्ध प्रविष्टियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- (vi) जब ऐसा पाठ्यक्रम अधिक वांछनीय हो तो विभागीय जांच से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को शॉर्टकट के रूप में पारित नहीं किया जाएगा।
- (vii) यदि गोपनीय अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी गई थी, तो यह अधिकारी के पक्ष में एक तथ्य है।
- (viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

15. कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज की वापसी (उपरोक्त), की बात करें तो यह एक सिविल सेवा अधिकारी का मामला था, जिसका अपने ए. सी. आर. में अनुकरणीय मूल्यांकन था और जिसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए भी अनुशंसित किया गया था और जो केंद्र सरकार के साथ संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए ए. सी. सी. द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया था। खुफिया ब्यूरो द्वारा दायर प्रतिकूल रिपोर्ट के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के कारण उनका शिकार किया गया था। प्रतिकूल रिपोर्ट को दरकिनार किए जाने और न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए निर्देश जारी किए जाने के बाद भी, एक सतर्कता निरीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर न्यायाधिकरण को नियुक्ति के लिए दी गई पूर्व मंजूरी को वापस लेने की मांग की गई थी। पुनः अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने सतर्कता मंजूरी को वापस लेने में हस्तक्षेप किया था, जिस पर कर्मचारी को संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारी के रूप में 'सहमत सूची' में रखा गया था और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने कम था और प्रधान आयुक्तों के पद पर पदोन्नति की सूची के प्रकाशन से ठीक पहले था। इन सम्मोहक तथ्यों में ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया गया था।

16. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश, जिसे उपरोक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई है, अनुलग्नक-7 में प्रस्तुत किया गया है, बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 74 (बी) (ii) को संदर्भित करता है जिसमें 14 व्यक्तियों को सेवानिवृत्त किया गया है। उन पर कोई कलंक नहीं लगाया गया है और इसे सजा का उपाय नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक हित का बयान हालांकि स्पष्ट नहीं है, नियम 74 (बी) (ii) के संदर्भ से स्पष्ट है।

17. उच्च न्यायालय के विद्वान स्थायी सलाहकार ने याचिकाकर्ता की अयोग्यता को साबित करने के लिए जवाबी हलफनामे का उल्लेख किया था, जिसके कारण उनकी अनिवार्य

सेवानिवृत्ति हो गई थी। जैसा कि **इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन** (उपरोक्त) में कहा गया है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सरकारी कर्मचारी पर केवल तभी कलंक लगाता है जब इसमें बयान शामिल हों। उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप लगाना; जिस स्थिति में उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले दंड के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। नियम का केवल एक संदर्भ; भले ही इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आधारों का उल्लेख हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को सजा के आदेश के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है; जिससे एक अलग इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

18. याचिकाकर्ता को दिनांक 19.06.2012 के आदेश द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से बिहार न्यायिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुसार, वह 16.08.2012 को न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में शामिल हुए। वर्ष 2019 में उनकी सेवाओं की पुष्टि की गई और उन्हें 12.12.2019 को सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर पदोन्नत किया गया। यह रिपोर्ट किए गए निर्णय के अनुसार है **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ (2002) 4 एस. सी. सी. 247** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक समिति थी 50, 55 से 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायिक अधिकारियों के अभिलेखों पर विचार करने के लिए पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति द्वारा गठित। समिति में J.A.D.-I और J.A.D.-I I शामिल थे और इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की थी। दिनांक 19.01.2018 के कार्यवृत्त के माध्यम से, लागू करने के लिए मानदंडों को अपनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था। नियम 74 (बी) (ii) के तहत न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों पर विचार करने के लिए, जो (i) एसीआर; (ii) पिछले दस वर्षों का निपटान; (iii) सतर्कता शिकायतें; (iv) विभागीय जांच; और (v) प्रशासनिक शिकायतों के आधार पर होना था। इसके अलावा, संबंधित न्यायिक अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड को भी गिना जाना था। माननीय

स्थायी समिति ने 16 अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिस पर पूर्ण न्यायालय ने 08.02.2022 को विचार किया। ये कार्यवाहियाँ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के साथ-साथ हुईं; जो समानांतर चल रही थीं।

19. पूर्ण पीठ द्वारा विशेष रूप से यह पाया गया कि किसी न्यायिक अधिकारी को 50,55 और 58 वर्ष की आयु में बने रहने के लिए विचार करते समय उसके ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि विषय नियम के तहत विचार के लिए मापदंड अलग थे; जिसमें अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड का समग्र मूल्यांकन आवश्यक था। अरुण कुमार गुप्ता (ऊपर) जाँच और स्थायी समिति द्वारा सामूहिक निर्णय के बाद एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक और मामला था, जैसा कि तत्काल मामला है। यह माना गया कि 'वॉश-ऑफ थ्योरी', जिसका अर्थ है, पदोन्नति से पहले का रिकॉर्ड उच्च पद पर पदोन्नति के बाद अपना स्टिंग खो देता है। न्यायिक अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी। कार्य निष्पादन का आकलन करने और स्थायी समिति और पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त समिति के निर्णय की जांच करने वाला न्यायालय निर्णय की अपील में नहीं बैठा है, जैसा कि टी. एस. नक्शबंदी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 592 में कहा गया है। यह समिति पूर्ण पीठ के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है या उसका स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है।

20. पूर्ण पीठ के समक्ष, जहाँ तक एक अधिकारी ने सिफारिश की थी, यह संकल्प लिया गया था कि उसे निलंबित कर दिया जाए और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय को स्थगित रखते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए। एक अन्य अधिकारी जिसकी सेवानिवृत्ति तीन महीने के भीतर हुई थी, उसे भी अनिवार्य रूप से

सेवानिवृत्त नहीं किया गया था क्योंकि उसे तीन महीने का नोटिस वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं था। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अनुशंसित अन्य 14 न्यायिक अधिकारियों को पूर्ण न्यायालय द्वारा निरंतरता के लिए अनुपयुक्त और मृत लकड़ी को हटाने के उपाय के रूप में त्वरित करने का संकल्प लिया गया था। याचिकाकर्ता उन अधिकारियों में से एक था जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गए थे।

21. हमें विशेष रूप से यह देखना होगा कि 16 मामले पूर्ण पीठ ने विशेष रूप से पाया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और दूसरे में, समिति का निर्णय आसन्न सेवानिवृत्ति के कारण अलग था। याचिकाकर्ता के मामले में, दर्ज किए गए एसीआर को कंडिका-15 में निकाला जाता है, जो इंगित करता है कि अधिकारी का मूल्यांकन 24.10.2019 को 'औसत' के रूप में किया गया है। 12.09.2020 को दर्ज बाद के ए. सी. आर. में, उन्हें 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन, उनके उत्पादन की गुणवत्ता और कानून के ज्ञान को 'औसत' के रूप में दर्ज किया गया था। जहाँ तक न्यायिक कार्य में उनके उद्योग और मामलों के त्वरित निपटारे और उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेने की इच्छा की बात है, रिपोर्टिंग अधिकारी की राय थी कि यह केवल 'कुछ हद तक' है। दोनों ए. सी. आर. में यह उल्लेख किया गया है कि उनके खिलाफ कई आरोप याचिकाएं दायर की गई हैं, जो जांच की प्रक्रिया में हैं।

22. पटना उच्च न्यायालय की किशोर न्याय की निगरानी समिति ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर विचार किया है, 08.09.2020 को आयोजित अपनी बैठक में, जो इंगित करता है कि प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, पटना (संक्षेप में 'जेजेबी') के रूप में उनका प्रदर्शन अक्सर वांछित था; कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए, मनमाने आदेश पारित करते हुए वह भी निहित स्वार्थ के साथ। याचिकाकर्ता ने जेजेबी, पटना के सामाजिक सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बनाए रखे, जिनके पास कई शिकायतें दर्ज कराईं।

23. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वास्तव में, सामाजिक सदस्यों की गलती थी और वे जेजेबी के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। हम नहीं देखते कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई शिकायत की गई है और न ही आरोप की पुष्टि की गई है। समिति ने यह भी दर्ज किया कि जेजेबी और अवलोकन गृह, पटना के दौरे पर जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और प्रधान दंडाधिकारी ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए थे। समिति की राय थी कि याचिकाकर्ता को तुरंत जेजेबी से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

24. निगरानी समिति की उपरोक्त रिपोर्ट को देखते हुए, याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही शुरू होने तक स्थायी समिति द्वारा निलंबित कर दिया गया था। पहला आरोप पत्र जारी होने के बाद, किशोर न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की निगरानी समिति की एक और रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता की सक्रिय मिलीभगत से जेजेबी पटना से दो मामलों के रिकॉर्ड गायब होने के बारे में स्थायी समिति के ध्यान में लाया, जिस पर अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए थे। याचिकाकर्ता ने 2022 के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. पर अपनी बैठक में अतिरिक्त प्रभार अनुच्छेद और स्थायी समिति को अपना बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत किया। 28.03.2022, संभवतः स्थायी समिति द्वारा याचिकाकर्ता के सेवा में बने रहने के कारण मामले को स्थगित रखने का संकल्प लिया गया।

25. कंडिका 22 पर जवाबी हलफनामा यह भी इंगित करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगभग 12 आरोप लगाए गए हैं। यह सच है कि अधिकांश कार्यवाही बंद कर दी गई थी। उल्लिखित आरोपों में से पहला, एक स्वामित्व मुकदमे में पारित एक फैसले के संबंध में था, जो याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली अदालत के आर्थिक अधिकार क्षेत्र से बाहर था। शिकायत को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया था कि राज्य ने अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी, और स्पष्ट रूप से न्यायिक आदेश के खिलाफ कोई

कार्यवाही नहीं हो सकती थी। 10.04.2018 दिनांकित एक अन्य आरोप याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता दलालों के माध्यम से रिश्वत प्राप्त कर रहा था और बाहरी विचारों के आधार पर मामलों का निपटारा कर रहा था। यह फिर से याचिकाकर्ता द्वारा तीन स्वामित्व मुकदमों में पारित न्यायिक आदेशों पर आधारित था, जिसके खिलाफ बिहार राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, जिसके कारण कार्यवाही बंद कर दी गई थी। 04.05.2018 को एक स्वामित्व मुकदमे में पारित एक अनुचित और आंशिक आदेश के संबंध में भी आरोप लगाया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एक अन्य आरोप याचिकाकर्ता द्वारा वादियों को अपनी पसंद के अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए मजबूर करने के संबंध में था, जिसे हस्ताक्षरित किया गया था। याचिकाकर्ता के छोटे भाई के माध्यम से झूठी शिकायत दर्ज करने के संबंध में आरोप इस कारण लगाया गया था कि आरोप याचिका का समर्थन करने वाला कोई हलफनामा नहीं था।

26. छठा आरोप एक अधिवक्ता द्वारा प्रधान दंडाधिकारी, जेजेबी पटना के रूप में याचिकाकर्ता के आचरण के खिलाफ लगाया गया था, विशेष रूप से मनमाने आदेश पारित करने के संबंध में; जिस पर जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना को याचिकाकर्ता को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में सतर्क रहने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया था। जिला न्यायाधीश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक महिला अधिवक्ता को गाली देने और अवैध और गैरकानूनी गतिविधि का आरोप लगाया गया। आरोप याचिकाओं की बाढ़ से संकेत मिलता है कि पीठासीन अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता के आचरण और उसके आदेशों के खिलाफ शिकायतें उठाई गई हैं; जो न्यायिक आदेशों के खिलाफ शिकायत, स्पष्ट रूप से, एक अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण नहीं बन सकती है। एक न्यायिक आदेश को एक अपील में उचित रूप से चुनौती दी जानी चाहिए और जब तक कि गलत आदेश पारित करने में बाहरी विचार का प्रमाण नहीं है, तब तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। हालाँकि, कई आदेश पारित किए गए जिन्होंने आरोपों को जन्म दिया, बिहार सेवा

संहिता के नियम 74 (बी) (ii) के तहत न्यायिक अधिकारी के बने रहने पर विचार करने के लिए एक वैध आधार है।

27. आठवाँ आरोप फिर से पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर जेजेबी, पटना में अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में था। अधिकारी के आचरण के संबंध में नौवां आरोप जेजेबी, पटना के रूप में अधिकारी के आचरण के संदर्भ में अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय था। जिस 10वें आरोप का उल्लेख किया गया था, वह पहले लगाए गए आरोप के समान था, जिसे खारिज कर दिया गया था। 11वीं और 12वीं शिकायत जेजेबी, पटना में अधिकारी के आचरण पर भी थी, जिसे भी हटा दिया गया था।

28. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि याचिकाकर्ता को 17.10.2019 पर पदोन्नत किया गया था, जाहिर है कि उसे उच्च पद पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त पाया गया था, जिसके बाद अचानक उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाया और याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। इस संदर्भ में, हम **प्यारे मोहन लाल** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हैं, जिसमें यह विशेष रूप से घोषित किया गया है कि ए. सी. आर. में केवल श्रेणीकरण, जो पदोन्नति के विचार के लिए प्रासंगिक हैं, एक निरंतरता को सक्षम नहीं करेगा, यदि कर्मचारी सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। यह सिद्धांत कि किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टियों को समाप्त हो जाएंगी, न्यायिक मामले में लागू नहीं होगा न्यायिक अधिकारी का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए योग्य है या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से क्योंकि ऐसी आकस्मिकता अधिकारी के पूरे सेवा अभिलेख पर आधारित है। **प्यारे मोहन लाल** (उपरोक्त) में पदोन्नति एक तदर्थ आधार पर थी। वर्तमान मामले में, हालांकि पदोन्नति की गई, उसके

तुरंत बाद उन्हें प्रधान दंडाधिकारी, जेजेबी पटना के रूप में तैनात किया गया। याचिकाकर्ता को 12.12.2019 को पदोन्नत किया गया और अवर-न्यायाधीश-III-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना शहर के रूप में तैनात किया गया, लेकिन फिर से जेजेबी, पटना में तैनात किया गया। यह स्थायी समिति के प्रस्ताव के अनुसार था, जिसने इस तरह की नियुक्ति को सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी, विशेष रूप से प्रधान दंडाधिकारी जेजेबी की निरंतरता के लिए।

29. प्रधान दंडाधिकारी, जेजेबी पटना के रूप में उनके आचरण के बारे में शिकायतें इसके बाद उत्पन्न हुईं, हालांकि पूर्व अवधि का भी उल्लेख करते हुए शिकायतें थीं। 12.09.2020 को उनकी गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज मूल्यांकन, अधिकारी की पदोन्नति के बाद था, लगभग राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग से 04.09.2020 दिनांकित मेल की प्राप्ति के साथ, जिसे स्थायी समिति के समक्ष नहीं रखा गया था। जेजेबी पटना में याचिकाकर्ता के कामकाज के संबंध में विभिन्न अनियमितताएं और जारी निर्देशों का पालन न करना। पटना उच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति की भी एक साथ बैठक हुई। पटना उच्च न्यायालय के किशोर न्याय निगरानी समिति की सिफारिश दिनांक 08.09.2020 को अधिकारी को हटाने के लिए की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 17.11.2019 को जारी समिति के निर्देशों का पालन न करने के कारण एक किशोर को बेरहमी से पीटा गया था।

30. काउंटर जवाबी हलफनामों में निकाले गए निगरानी समिति के कार्यवृत्त को नीचे दिया गया है:

"समिति को प्रधान दंडाधिकारी, जेजेबी, पटना के खिलाफ बार-बार शिकायतें मिल रही हैं। श्री संजीव कुमार चंद्रियावी कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करने, मनमाने आदेश पारित करने, निहित स्वार्थ के साथ आदेश पारित करने

आदि के अपने कार्य से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बोर्ड से ऊपर नहीं था और वह बहुत अधिक आरोप लगाने वाला है।

इन आरोपों के अलावा, जे. जे. बोर्ड, पटना के सामाजिक सदस्यों ने भी मामूली मुद्दों पर भी उनके व्यवहार के बारे में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं।

हाल ही में जे. जे. एस. को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक से 04.09.2020 को एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें जे. जे. बी., पटना के कामकाज के बारे में एक रिपोर्ट है और इसमें गंभीर अनियमितताओं को दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सामाजिक सदस्यों और प्रधान दंडाधिकारी के बीच टकराव है जो किशोर न्याय बोर्ड, पटना के समग्र कामकाज को प्रभावित कर रहा है।

समिति ने 17 नवंबर 2019 को किशोर न्याय बोर्ड और संप्रेक्षण गृह पटना का निरीक्षण किया। नवम्बर में भी कई अनियमितताएं पाई गईं और इस संबंध में इसे हटाने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए लेकिन किशोर न्याय सचिवालय द्वारा प्राप्त बाद की शिकायतें पर्याप्त रूप से इंगित करती हैं कि उनका पालन नहीं किया गया है। समिति ने निरीक्षण के दौरान निरीक्षण गृह में अधिक आयु के कैदियों रहने से संबंधित मुद्दों पर भी गौर किया लेकिन उन कैदियों को रखने की प्रथा अभी भी जारी है, जिसके कारण कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें हाल ही की घटना भी शामिल है जिसमें निरीक्षण गृह पटना के कुछ अन्य कैदियों द्वारा एक किशोर की बेरहमी से पिटाई की गई और समाचार पत्रों में इसकी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई।

इस प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड, पटना के प्रधान दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार चंद्रियावी के आचरण और उनके खिलाफ प्राप्त आरोपों की प्रकृति पर

विचार करते हुए, समिति की राय है कि उन्हें तत्काल प्रधान दंडाधिकारी जे.जे.बी. पटना के पद से मुक्त किया जाना चाहिए और उनके स्थान पर एक अपयुक्त अधिकारी को वहाँ पदस्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में उचित निर्णय के लिए मामले को स्थायी समिति के समक्ष रखा जाए।”

31. इन टिप्पणियों को 15.10.2020 को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यद्यपि याचिकाकर्ता के खिलाफ जेजेबी पटना में उसके आचरण के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन उसका मामला भी उक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष जारी रखने के लिए विचार के लिए आया; जो उसके खिलाफ कथित कदाचार के परिणामस्वरूप नहीं था। यह उस परिस्थिति में था कि निलंबन का आदेश और जांच को स्थगित कर दिया गया और कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय के अनुसार, उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

32. हम गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम मजदूर सभा (1980) 2 एस. सी. सी. 593 का संदर्भ लेंगे, जिसमें शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 831 से उद्धृत करने के बाद, यह माना गया था:

“53. मालिकों और नौकरों को बर्खास्तगी के कानून के साथ लुका-छिपी खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और स्पष्ट और उचित मानदंडों को शब्दावली कवर-अप या मानसिक प्रक्रियाओं के लिए अपील द्वारा गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आदेश के मूल कारण पर आधारित होना चाहिए, चाहे खुलासा किया गया हो या अज्ञात। न्यायालय समाप्ति के औपचारिक आदेश से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों या दस्तावेजों से पता लगाएगा कि समाप्ति के लिए सही आधार क्या है। यदि, इस प्रकार जांच की

जाती है, तो आदेश के कारण या परिणाम में दंडात्मक स्वाद होता है, तो यह बर्खास्तगी है। यदि यह इस परीक्षण से कम हो जाता है, तो इसे सजा नहीं कहा जा सकता है। इसे थोड़ा अलग तरीके से कहने के लिए, एक समाप्ति प्रभावी है क्योंकि स्वामी दुराचार और अपराधी सेवक की सेवा को समाप्त करने की परिणामी वांछनीयता से संतुष्ट है, एक बर्खास्तगी है, भले ही उसे स्थायी आदेश के तहत एक निर्दोष आदेश के साथ समाप्त करने का कानूनी अधिकार था या अन्यथा। क्या, ऐसे मामले में आधार औपचारिक आदेश से अलग कार्यवाही में दर्ज किए जाते हैं, यह इसकी प्रकृति से अलग नहीं है। न ही यह तथ्य कि, अपराध से संतुष्ट होने के बाद, स्वामी जांच को छोड़ देता है और समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। एक कथित कदाचार और उसके और सेवा की समाप्ति के बीच एक जीवंत संबंध को देखते हुए निष्कर्ष यह है कि बर्खास्तगी, भले ही साधारण समाप्ति पर पूर्ण लाभ दिए गए हैं और गैर-हानिकारक शब्दावली का उपयोग किया गया हो।”

“54. इसके विपरीत, भले ही कदाचार का संदेह हो, स्वामी कह सकता है कि वह इसके बारे में परेशान नहीं करना चाहता है और अपने अपराध में नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा महसूस कर सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रख रहा है जिससे वह खुश नहीं है। हो सकता है कि वह जाँच करना पसंद न करे और न ही एक संदिग्ध नौकर को बनाए रखने का जोखिम उठाए। फिर यह बर्खास्तगी नहीं है, बल्कि समाप्ति सरल है, यदि कारणों का कोई हानिकारक अभिलेख या उसके पूर्ण अंतिम लाभों पर दंडात्मक आर्थिक कटौती नहीं पाई जाती है। वास्तव में, कदाचार तब निर्वहन में गतिशील कारक नहीं है। हमें यहां अन्य काल्पनिक स्थितियों का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है।”

33. हम संतुष्ट हैं कि यहाँ, कंडिका 54 लागू होता है, क्योंकि विशिष्ट आरोप के बिना भी, याचिकाकर्ता के मामले को उसके बने रहने पर विचार के लिए लिया जाता। यह केवल विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिश पर था कि स्थायी समिति ने जांच को लंबित रखा और पूर्ण पीठ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के लिए आगे बढ़ी। सभी 16 व्यक्तियों की इस तरह से सिफारिश की गई थी और उनमें से दो को कठोरता से मुक्त कर दिया गया था, जिनमें से एक इस आधार पर था कि जांच की जानी चाहिए। हालाँकि यहाँ पूर्ण पीठ की राय थी कि, समग्र मूल्यांकन को देखते हुए, अधिकारी को दरवाजा दिखाया जाना चाहिए; गैर-कलंकित और गैर-दंडात्मक, कदाचार के आरोप से प्रेरित नहीं, इस प्रकार यह बर्खास्तगी सरलीकरण है।

34. हम पहले ही मान चुके हैं कि आदेश दंडात्मक नहीं है और नियम 74 (ii) विशेष रूप से 30 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद, 50 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद या उसके बाद किसी भी तारीख को सार्वजनिक हित में कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता है। जाँच के साथ-साथ, याचिकाकर्ताओं का मामला जारी रखने के लिए विचार के लिए आया; जो न्यायिक अधिकारियों के मामले में अनिवार्य है। गठित विशेष समिति ने विभिन्न मानकों पर गौर किया और स्वतंत्र रूप से याचिकाकर्ता को समग्र विचार के बाद सेवा से अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी पाया। लिया गया निर्णय याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं था और इसमें 15 अन्य शामिल थे। जिस स्तर पर जांच की गई थी, वह उस संदर्भ में अप्रासंगिक है और हालाँकि जिस शिकायत पर जांच शुरू की गई थी, वह समिति के साथ भी जुड़ी हुई होगी, लेकिन अधिकारी का ट्रैक पिछले कार्य निष्पादन अभिलेख से ऊपर नहीं था। यह समिति की सिफारिश के आधार पर था कि स्थायी समिति ने जांच को स्थगित रखने का फैसला किया।

35. नियम 74 (बी) (आई) का प्रावधान इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लागू नहीं होता है कि सरकार कर्मचारी को निरंतरता के लिए अनुपयुक्त पाती है। नियम 74 (बी) (आई) सरकारी सेवक की उनके अनुरोध पर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में है। परंतुक इंगित करता है कि निलंबन के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के अलावा सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होगा। उक्त परंतुक केवल तभी लागू होता है जब एक सरकारी कर्मचारी जिसके खिलाफ कार्यवाही लंबित है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है; अनुशासनात्मक कार्यवाही से छूट के रूप में अधिक। यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह केवल इस परिस्थिति में है कि परंतुक सरकार को उठाए गए आरोपों पर गौर करने और यह तय करने में सक्षम बनाता है कि क्या जांच पूरी की जानी है या सरकारी कर्मचारी को उसके अनुरोध पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है। वास्तव में, दूसरा परंतुक पटना उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के अनुरोध पर ऐसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को केवल मुख्य न्यायाधीश के विशिष्ट अनुमोदन के साथ सक्षम बनाता है; मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के स्थान पर कदम रखा है, जहां तक पटना उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का संबंध है। उक्त परंतुक याचिकाकर्ता पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति उसके अनुरोध पर नहीं थी, बल्कि अनुपयुक्तता के निष्कर्ष पर थी।

36. विद्वान वरिष्ठ सलाहकार का यह भी अनुरोध है कि याचिकाकर्ता पेंशन का हकदार नहीं होगा, जो किसी भी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए नियम 74 के तहत एक आवश्यक आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा को प्रभावित नहीं करता है और वह सभी सेवानिवृत्त लाभों का हकदार होगा और कठोरता केवल तब तक है जब अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती

है। जहां तक पेंशन लाभों का संबंध है, नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से प्रभावित नहीं होना और सेवानिवृत्ति पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए उनकी पात्रता केवल इस शर्त पर है कि उन्होंने न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है। याचिकाकर्ता अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण पेंशन से वंचित नहीं है, बल्कि इस कारण से है कि उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय उसके पास न्यूनतम योग्यता सेवा नहीं थी। यह स्थिति नहीं हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसके पास सेवानिवृत्ति पर पेंशन को सक्षम करने वाली न्यूनतम योग्यता सेवा नहीं है, उसे नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद कि वह निरंतरता के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है और सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

37. याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि उन्हें तीन महीने के नोटिस वेतन का भुगतान नहीं दिया गया तथा और अपने निलंबन की अवधि के दौरान वेतन का केवल 50 प्रतिशत प्राप्त कर रहे थे। याचिकाकर्ता के निलंबन को स्थगित कर दिया गया और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसलिए, वह नियम 74 (बी) (ii) के तहत निर्धारित तीन महीने की अवधि के दौरान नोटिस वेतन पाने का हकदार है। यदि याचिकाकर्ता, को नोटिस अवधि के पूरे वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया गया, तो वह तीन महीने की नोटिस अवधि के बदले में पूरे वेतन और भत्तें पाने का हकदार होगा।

38. जहाँ तक निलंबन अवधि की बात है, इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इसे किस प्रकार माना जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने जांच छोड़ दी थी और न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का फैसला किया था, जो दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों

में, याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के दौरान देय पूरे वेतन का हकदार है। याचिकाकर्ता को निलंबन अवधि के दौरान देय वेतन की शेष राशि और उपरोक्त अवधि के लिए भुगतान किए गए किसी भी निर्वाह भत्ते में कटौती करने के बाद तीन महीने की नोटिस अवधि के लिए देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

39. रिट याचिका को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

40. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

पी.के.पी/सुजीत

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।